Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding demand for CBI enquiry on the expenditure of the funds allocated to Rajasthan Government under Jal Jiwan Mission

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरा विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट दे दीजिए। ... (व्यवधान) जल जीवन मिशन के तहत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी का विजन है कि हर घर को 'नल से जल' मिले। यह काम वर्ष 2024 तक हो, इसलिए सभी राज्य सरकारों को मदद देने का प्रावधान रखा गया है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वह इसे समय पर खर्च नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही जब राशि खर्च करने की बात आई, तो अभी हाल ही में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स जारी किए गए, उनमें उनकी जो बीएसआर की रेट है, वह 43 परसेंट ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उसमें जो बंदिश थी कि टेंडरार साइट विजिट करके एक्शन का सर्टिफिकेट लेगा और उसे साथ सब्मिट करेगा, तो जितने भी टेंडर्स वाले हैं, जब उनको यह पता चला, तो उसकी वजह से यह 43 परसेंट ज्यादा आया।

सर, इसका कारण यह है कि भारत सरकार का उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा है और 50 प्रतिशत हिस्सा स्टेट का है। लेकिन इसके अलावा 10 प्रतिशत मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को देना पड़ेगा, उनके ऊपर 10 प्रतिशत का भार पड़ेगा। इसमें सैकड़ों-करोड़ों रुपयों का गड़बड़झाला है।

मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, जो यहां विराजमान हैं, वे इस विषय की इंक्वायरी करें, इसकी जांच करें और यह मामला सीबीआई को दें।

धन्यवाद।